सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

#MODIfied100

100 दिन

गृह मंत्रालय की उपलब्धियां

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

#MODIfied100

100 दिन

गृह मंत्रालय की उपलब्धियां

सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

संसद की सिफारिश पर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के अंतर्गत एक घोषणा जारी की गई

- **अनुच्छेद 370** को निरस्त किया गया
- भारत के संविधान के सभी प्रावधान बगैर किसी संशोधनों अथवा अपवादों के जम्मू और कश्मीर में लागू होंगे

अनुच्छेद 370 (1) के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 जारी किया गया

- **अनुच्छेद 35ए** हटाया गया
- भारत के संविधान के सभी प्रावधान बगैर किसी संशोधनों अथवा अपवादों के जम्मू और कश्मीर में लागू होंगे

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 एक अधिनियम बन गया

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

- जम्मू और कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक रह रहे लोगों को नियत्रंण रेखा पर रह रहे लोगों को मिले आरक्षण की भांति **3% का आरक्षण** दिया गया

अमरनाथ यात्रा 2019

- 3,42,883 यात्रियों ने सुरक्षित और संरक्षित तरीके से दर्शन किए
- यह वर्ष 2018 की तुलना में **लगभग 20% अधिक** है

सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

आतंक पर कठोर कार्रवाई

#MODIfied100

100 दिन

गृह मंत्रालय की उपलब्धियां

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम, 2008 को संशोधित किया गया

- **एनआईए को विदेश में भारतीय नागरिकों/संपत्ति से संबंधित** आतंकवादी मामलों की जांच करने के लिए अधिकार दिये गए
- **एनआईए के अधिदेश का विस्तार** – विस्फोटक पदार्थ, मानव तस्करी, प्रतिबंधित हथियारों का विनिर्माण/विक्रय और साइबर आतंकवाद जैसे नये अपराधों को इसकी अनुसूची में शामिल किया गया

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 को संशोधित किया गया

- केन्द्र सरकार को किसी **व्यक्ति विशेष को आतंकवादी नामित करने** की शक्तियां प्रदान की गई
- एनआईए को आतंकवाद से अर्जित संपत्ति जब्त करने की शक्तियां प्रदान की
- न्यूक्लियर आतंकवाद से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कनवेंशनों का अनुपालन किया गया
- यूएपीए के वर्तमान संशोधन के पश्चात चार व्यक्तियों – **मौलाना मसूद अज़हर, हाफिज़ मुहम्मद सईद, ज़की उर रहमान लख्वी और दाऊद इब्राहिम** को आतंकवादी घोषित किया गया
- न्यूयार्क स्थित **'सिख फॉर जस्टिस' (एसएफजे)** को यूएपीए, 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत 10.07.2019 की अधिसूचना द्वारा विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया गया

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का शुभारंभ

- **नागरिक केन्द्रित पहल** – www.cybercrime.gov.in
- आम जनता, पुलिस स्टेशन जाए बगैर सभी साइबर अपराधों को रिपोर्ट कर सकती है
- संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियों को **शिकायतें आनलाईन सुलभ** होंगी

अष्ठलक्ष्मी

#MODIfied100

100 दिन

गृह मंत्रालय की उपलब्धियां

सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

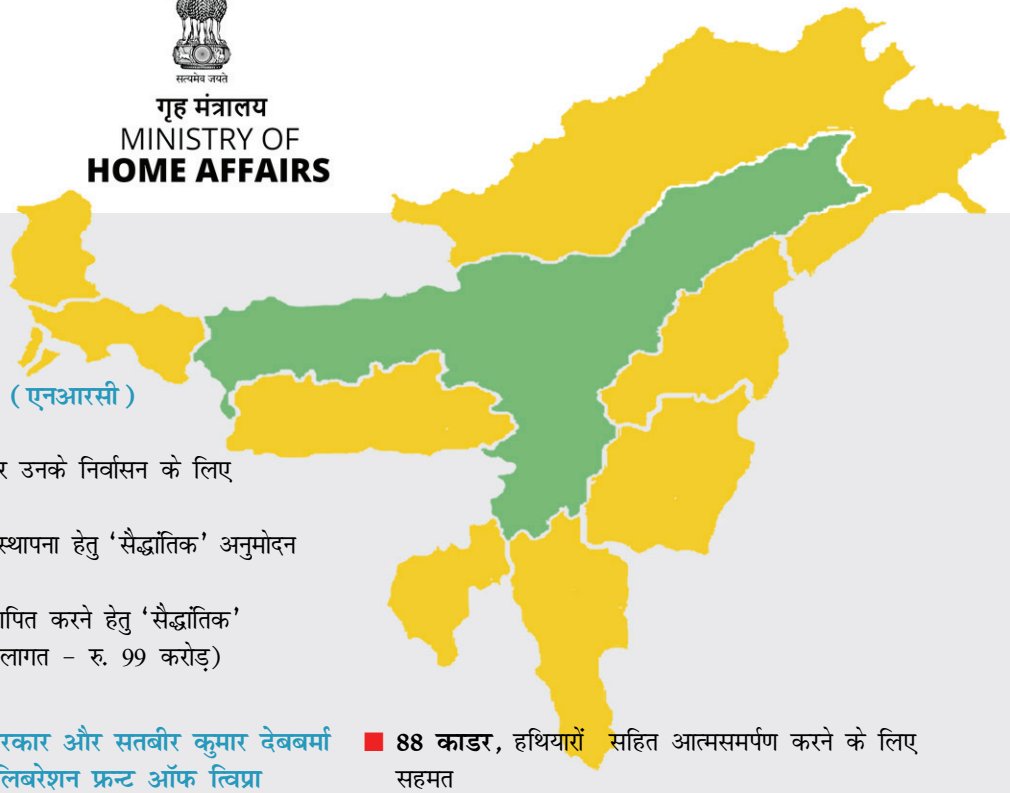

असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) 31.08.2019 को प्रकाशित किया गया

- **अवैध आप्रवासियों** का पता लगाने और उनके निर्वासन के लिए तंत्र बनाया गया
- **1000 फॉरेनर्ज़ ट्रिब्यूनल (FT)** की स्थापना हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया गया
- असम सरकार को **e-FT प्लेटफार्म** स्थापित करने हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया गया (अनुमानित लागत – रु. 99 करोड़)

भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और सतबीर कुमार देबबर्मा द्वारा संचालित नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्विप्रा (एनएलएफटी-एसडी) द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए

- **एनएलएफटी-एसडी हिंसा का रास्ता छोड़ने,** मुख्यधारा में शामिल होने और भारत के संविधान को मानने के लिए सहमत
- **88 काडर,** हथियारों सहित आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत
- **काडरों को आत्मसमर्पण- सह-पुनर्वास योजना, 2018** के तहत आत्मसमर्पण के लाभ प्राप्त होंगे। त्रिपुरा सरकार आत्मसमर्पण करने वालों काडरों को उनके आवास, भर्ती, शिक्षा आदि के कार्य में सहायता प्रदान करेगी।
- भारत सरकार त्रिपुरा के **जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास** के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करेगी

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

आपदा प्रबंधन

#MODIfied100

100 दिन

गृह मंत्रालय की उपलब्धियां

इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इनफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) की स्थापना की गई

- अवसंरचना के आपदा एवं विपत्ति प्रतिरोधी विभिन्न पहलुओं पर जानकारी के **आदान प्रदान हेतु प्लेटफार्म**
- जोखिम संदर्भ और आर्थिक जरूरतों पर आधारित **अवसंरचना के विकास हेतु** अन्य देशों की सहायता
- स्टेक होल्डरों की **प्रोद्योगिकीय विशेषज्ञता** का पूल बनाना
- प्रधानमंत्री 23 सितंबर 2019 को न्यूयार्क में यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान **CDRI का शुभारंभ** करेगें

अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय दल (IMCT) के तत्काल दौरे

- IMCT द्वारा राज्यों से ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बगैर बाढ़ प्रभावित राज्यों का मौका मुआयना करने हेतु **प्रारंभिक दौरा** किया जाएगा
- IMCT राज्यों से ज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात विस्तृत **नुकसान का आकलन** करने हेतु दोबारा दौरा करेगी

राष्ट्र का गौरव हमारे सुरक्षा बल

#MODIfied100

100 दिन

गृह मंत्रालय की उपलब्धियां

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

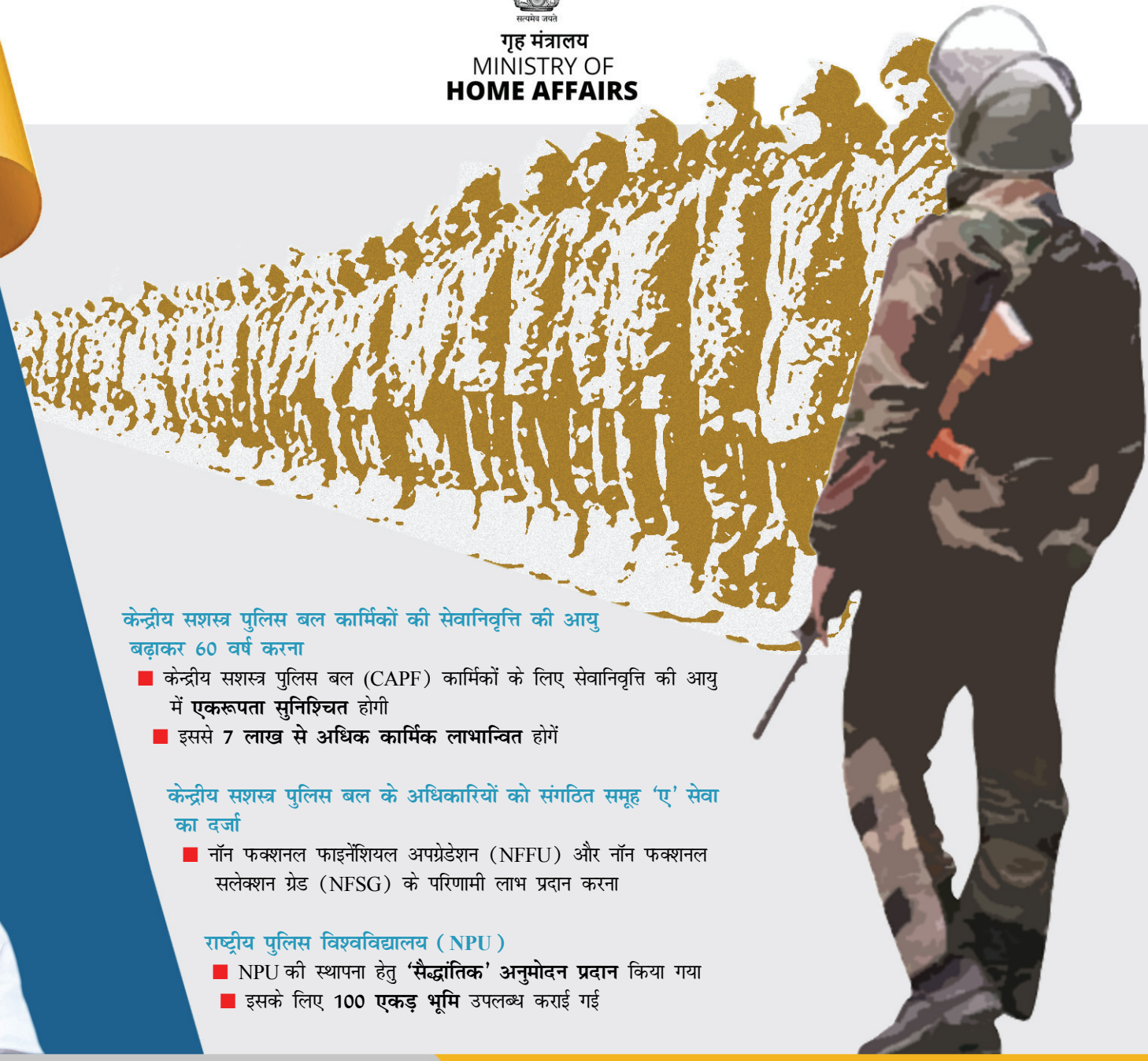

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करना

- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु में **एकरूपता सुनिश्चित** होगी
- इससे **7 लाख से अधिक कार्मिक लाभान्वित** होगें

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों को संगठित समूह 'ए' सेवा का दर्जा

- नॉन फक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (NFFU) और नॉन फक्शनल सलेक्शन ग्रेड (NFSG) के परिणामी लाभ प्रदान करना

राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय (NPU)

- NPU की स्थापना हेतु **'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान** किया गया
- इसके लिए **100 एकड़ भूमि** उपलब्ध कराई गई

सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

कोई भी नागरिक नहीं छूटेगा

#MODIfied100

100 दिन

गृह मंत्रालय की उपलब्धियां

जनगणना एप और जनगणना पोर्टल का शुभारंभ

- **प्री-टेस्ट डाटा कलेक्शन हेतु** 12.08.2019 से शुरू किए गए **मोबाइल एप** को गूगल प्ले स्टोर पर रिलीज़ किया गया
- **जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी पोर्टल (CMMP)** चालू किया गया

सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

#MODIfied100

100 दिन

गृह मंत्रालय की उपलब्धियां

मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और गरीब कल्याण का पर्याय है। मोदी सरकार देश के हर वर्ग की आशाओं की प्रतीक है। अपने द्वितीय कार्यकाल के 100 दिनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिसकी राह हर देशवासी 70 सालों से देख रहा था।

अमित शाह
केन्द्रीय गृह मंत्री